

संक्षेपाक्षर

एबीआई	कृषि व्यवसाय इंक्यूबेटर	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
सीएजीआर	चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर	एनएएआरएम	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी
सीईपीए	व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता	नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
क्राफिकार्ड	कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्थाओं हेतु समीक्षा समिति	एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
सी-एसआईटीई	साइबर-सुरक्षा सूचना प्रौद्योगिकी जांच	एनआईई	राष्ट्रीय कार्यान्वयनकर्ता इकाई
डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	ओएफपीओ	कृषीतर उत्पादक संगठन
डीआईडीएफ	डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना निधि	पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
एफपीओ	कृषक उत्पादक संगठन	पीएमएवाई-जी	प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण
विव	वित्तीय वर्ष	आर एंड डी	अनुसंधान और विकास
जीबी	ग्रामीण बैंक	आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
जीएलसी	आधारस्तरीय ऋण	आरबीआईसी	ग्रामीण कृषि व्यवसाय उद्भवन केंद्र
जीओआई	भारत सरकार	आरसीबी	ग्रामीण सहकारी बैंक
जीवीए	सकल मूल्य वर्धन	आरएफआई	ग्रामीण वित्तीय संस्था
एचए	हेक्टेयर	आरआईडीएफ	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आईसीआरआईएसएटी	इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रोपिक्स	एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
आईआईएमआर	भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान	एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
आईपीसीसी	इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज	एसई	पर्यवेक्षित संस्था
जेएलजी	संयुक्त देयता समूह	एसएफबी	लघु वित्त बैंक
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड	एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एलईडीपी	आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम	एसएलएफ	विशेष चलनिधि सुविधा
एलटी	दीर्घावधि	एसटी	अल्पावधि
एमईडीपी	सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम	एसटी (एसएओ)	अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन)
एमएफपी	मेगा फूड पार्क	एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
		टीडीएफ	जनजाति विकास निधि

नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट- 2021-22 के लिए नोट

- विवकैलेंडर वर्ष से पहले उल्लिखित उस वर्ष को दर्शाता है जिसमें वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, उदाहरणार्थ विव 2022, 31 मार्च 2022 को समाप्त होता है.
- संभव है कि पूर्णांकन के परिणामस्वरूप, तालिकाओं में इंगित संख्याओं के योग का मिलान न हो. आंकड़ों के प्रतिशत को 100% करने के लिए समायोजित किया गया है.
- चूंकि संवितरण चरणबद्ध तरीके से किया जाता है इसलिए संवितरण की राशि में पिछले वित्तीय वर्ष की परियोजना की राशि शामिल हो सकती है, इसलिए किसी विव के संवितरण उस विव की मंजूरी के अनुरूप नहीं हैं.
- नाबार्ड द्वारा परिभाषित क्षेत्र
दक्षिण: आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडू, पुदुच्चेरी और लक्षद्वीप
पश्चिम: गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, तथा दमन और दीव
उत्तर: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़
मध्य: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, और उत्तराखंड
पूर्व: बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
पूर्वोत्तर: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम